अशोका एक्सप्रेस

ASHOKA
SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress
E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

• वर्ष: 29 • अंक : 25 • नई दिल्ली • 09 से 15 जुलाई 2026 • पृष्ठ : 8 • मूल्य : 2 रूपये

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को तैयार जालंधर, 17 तारीख को करेंगे कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन

नीट के बाद यूजीसी-नेट भी लीक! राहुल गांधी का आरोप, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका जताई है। कांग्रेस सांसद का यह आरोप तब आया है, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के सोशियोलॉजी पेपर में शामिल हुए कई उम्मीदवारों ने परीक्षा के पेपर में व्याकरण और स्पेलिंग की गलतियों की शिकायत की थी। नीट यूजी पेपर लीक के कारण देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद गांधी ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। इन प्रदर्शनों में छात्रों, विपक्ष और छात्र संगठनों ने सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की है। बुधवार को एक्स पर गांधी ने यूजीसी-

नेटसोशियोलॉजी पेपर से जुड़े कई आरोपों का ज़िक्र किया। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि पेपर लीक हो गया था और भारत के कुछ हिस्सों में इसे कुल 2.25 लाख में बेचा जा रहा था। गांधी ने एक्स पर लिखा कि यूजीसी-नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पेज की एक पीडीएफ सर्कुलेट की गई थी। यह पीडीएफ क्वेश्चन पेपर सेट करने से जुड़ी है, जो सिर्फ़ एनटीए के पास होता है। पीडीएफ में लगभग 90 सवाल असली सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर के सवालों से मेल खाते हैं। यही क्वेश्चन पेपर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में 2.25 लाख में बेचा जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यही नेटवर्क CSIR-NET, HTET और एडीए जैसी परीक्षाओं के लिए भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा रहा था। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि NEET और NET में बार-बार हुए घोटालों के बावजूद मोदी सरकार आँखें मूंदे हुए है और चैन की नींद सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की सालों की कड़ी मेहनत–दिन-रात एक करके की गई पढ़ाई–उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि 30 जून की परीक्षा से पहले ही यूजीसी-नेट का प्रश्नपत्र लीक हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, रोहतक में दो छात्र नेताओं ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कथित समाजशास्त्र प्रश्नपत्र की सामग्री स्क्रीन पर दिखाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवारों को प्रश्नों के दो सेट पढ़ाए गए थे, और 100 प्रश्नों के उन सेटों में से एक सेट परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाता है। यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

440 करोड़ रुपये फीज, टीएमसी से जुड़े केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई

कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई ने हलचल बढ़ा दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के फंड से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है. जांच का केंद्र उन बैंक खातों को बनाया गया है, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं. ईडी की कई टीमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में राय के अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीएमसी से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 440 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज कर दी है. ईडी की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, जिन स्थानों पर छापेमारी की गई है, उनमें एक निजी एविएशन कंपनी का दफ्तर भी शामिल है. आरोप है कि यह कंपनी पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम भी लिया जा रहा है, को चार्टर्ड विमान उपलब्ध कराती थी. जांच एजेंसी अब इन वित्तीय लेनदेन और फंड के स्रोतों की पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि इन बैंक खातों को लेकर विवाद विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सामने आया था. पार्टी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने बैंक को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि खातों में जमा राशि का दुरुपयोग हो सकता है. इसके बाद टीएमसी के बागी गुट ने भी पश्चिम बंगाल पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि इन खातों में भ्रष्टाचार और कथित जबरन वसूली से जुटाया गया पैसा जमा है. दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिया था, जिससे फिलहाल कोई भी गुट इस राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकता.

दिल्ली में फिर रोडरेज- बीच सड़क टैक्सी ड्राइवर की गुंडागर्दी, कार टकराई और डंडा उठाया

नई दिल्ली । दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में बीती शाम रोडरेज की एक घटना सामने आई। पुलिस को इस संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी वैगनआर कार की एक सफेद मारुति अर्टिगा टैक्सी से हल्की टक्कर हो गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, टक्कर के बाद टैक्सी चालक ने डंडे से हमला करने का प्रयास किया। बचाव में शिकायतकर्ता ने टैक्सी चालक को धक्का दिया। इससे टैक्सी चालक पास खड़ी एक किआ सेल्टोस कार से टकरा गया। किआ सेल्टोस को मामूली नुकसान हुआ। घटना के बाद टैक्सी चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाही है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। फरार टैक्सी चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना द्वारका एक्सप्रेसवे टनल के भीतर हुई। टक्कर के बाद टैक्सी चालक का आक्रामक व्यवहार रोडरेज का कारण बना। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, तब तक टैक्सी चालक वहां से जा चुका था। पुलिस ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से टैक्सी के नंबर और चालक की पहचान की जा रही है। इस तरह की घटनाएं सड़क सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।

नरेला की खतरनाक जेल का नया मॉडल-एआई कैमरा-जैमर और वर्चुअल कोर्ट सब होगा अंदर, बाहर निकलना होगा मुश्किल

नई दिल्ली ।राजधानी में हाई-रिस्क कैदियों की सुरक्षा और निगरानी का तरीका पूरी तरह बदलने की तैयारी है। नरेला में बनने वाली हाई-सिक्योरिटी जेल एक नई जेल नहीं होगी, बल्कि तकनीक आधारित कारागार प्रबंधन का ऐसा मॉडल होगी, जिसमें कैदियों की निगरानी, आवाजाही, पेशी और सुरक्षा से जुड़ी लगभग हर प्रक्रिया डिजिटल और स्वचालित प्रणाली के जरिये संचालित होगी। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की सहायता देगी, जबकि शेष लागत दिल्ली सरकार वहन करेगी।तिहाड़ जेल देश के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। यहां लंबे समय से क्षमता से दो गुना करीब 20 हजार कैदी रखे जा रहे हैं। इससे सुरक्षा प्रबंधन, निगरानी और पुनर्वास व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। आतंकवाद, संगठित अपराध के हाई-रिस्क कैदियों को अदालत में पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना रहता है। नई हाई-सिक्योरिटी जेल का उद्देश्य ऐसे कैदियों को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में रखना है। अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य नरेला हाई-सिक्योरिटी जेल को केवल एक नई जेल के रूप में विकसित करना नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप तकनीक आधारित कारागार प्रबंधन के मॉडल के तौर पर स्थापित करना है। इस जेल की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इसे विशेष रूप से हाई-रिस्क कैदियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक कैदी को अलग सेल में रखा जाएगा, ताकि उनके बीच संपर्क, गैंग नेटवर्किंग और जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों की संभावना न्यूनतम रहे। पूरे परिसर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरे, बॉडी-वॉर्न कैमरे, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल, ऑटोमैटिक लॉकिंग सिस्टम, फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर और मोबाइल सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। जेल परिसर में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और इन-हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिससे हाई-रिस्क कैदियों को हर पेशी के लिए जेल से बाहर ले जाने की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। इससे सुरक्षा बलों पर दबाव घटने के साथ रास्ते में होने वाले सुरक्षा जोखिमों को भी कम किया जा सकेगा।

एनसीआरटी की पुस्तकों में संशोधन- हिटलर के संदर्भ हटाए गए, विभाजन पर कांग्रेस के रुख में बदलाव किया गया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीआरटी ने कक्षा 8 के सोशल साइंस की किताब में कई अहम बदलाव किए हैं। सबसे जरूरी बदलाव न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर में किया गया। इसके अलावा इस किताब से 1947 के बंटवारे पर कांग्रेस के रुख और एडॉल्फ हिटलर की नाजी विचारधारा के जिक्र को हटाना गया। नए वर्जन एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका से जुड़े पुराने कंटेंट को आपत्तिजनक बताया था और उसकी सभी फिजिकल और डिजिटल कॉपी वापस लेने का निर्देश दिया था। नई किताब में भारत की आजादी और बंटवारे से जुड़े इतिहास के चैप्टर में भी बदलाव किए गए हैं। अहम बदलावों में से एक बंटवारे पर कांग्रेस के रुख से जुड़ा है। पुरानी किताब में कहा गया था कि हालांकि महात्मा गांधी और कांग्रेस के यादातर नेताओं ने बंटवारे का विरोध किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानकर स्वीकार कर लिया। नए वर्जन में कहा गया है कि बंटवारे का कांग्रेस ने भी जोरदार विरोध किया था और यह भी कहा गया है कि क्या इसे स्वीकार करना आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था, यह बहस का विषय है। नए वर्जन में पुरानी किताब का एक वाक्य भी हटा दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि बंटवारे के दौरान जब पूरे उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक नरसंहार हो रहा था, तब कांग्रेस नेता बेबस थे। एक और अहम बदलाव स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की कोशिशों के बारे में है। पहले वाले एडिशन में कहा गया था कि बोस ने एडॉल्फ हिटलर का समर्थन मांगा था और जर्मन नेता को एक तानाशाह बताया था, जिसकी नस्लवादी नाजी विचारधारा और विस्तारवादी लक्ष्यों ने युद्ध शुरू किया था। इसके बजाय, बदली हुई किताब में कहा गया है कि बोस ने ब्रिटिश-विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था, इसमें हिटलर या नाजी विचारधारा का कोई जिक्र नहीं है। इतिहास वाले चैप्टर को भी बढ़ाया गया है और इसमें विनायक दामोदर सावरकर का जिक्र शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर चर्चा के दौरान 1925 में वीडी सावरकर ने भी स्वराज की ऐसी ही मांग की थी। बदली हुई किताब में सुप्रीम कोर्ट के दखल के कुछ महीनों बाद आई है, जिसमें न्यायपालिका पर एक चैप्टर में भ्रष्टाचार, अदालतों में लंबित मामलों और जजों के खिलाफ शिकायतों पर चर्चा की गई थी।

अभिजीत दीपके बोले- सीजेआई की टिप्पणी से हुआ सीजेपी का गठन, 24 घंटे में मिले 30 हजार सदस्य

नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कथित तौर पर सरकार की आलोचना करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद एक अनोखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिजीत दीपके ने इस टिप्पणी पर एक्स पर एक वायरल पोस्ट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिपके ने कहा कि उनका मकसद कोई छात्र आंदोलन शुरू करना नहीं था। 30 साल के दीपके ने इस विचार को कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक पैरोडी प्लेटफॉर्म में बदल दिया। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च होने के 24 घंटे के भीतर ही

30,000 से ज्यादा सदस्य मिल गए। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैली और युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि कुछ युवा सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन वे देश के विकास में कोई योगदान नहीं देते। इस टिप्पणी को कई लोगों ने युवाओं के प्रति अपमानजनक माना। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कई युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने का प्रयास बताया। अभिजीत दीपके ने मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी को व्यंग्यात्मक रूप से लिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर इस पर प्रतिक्रिया दी।

चढ़ावा चोरी पर राजनीति !

अयोध्या में श्रीराम मन्दिर तीर्थ क्षेत्र के लिए बने न्यास (ट्रस्ट) की बैठक में इसके महासचिव चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिये जाने के बाद यह फैसला किया गया कि मन्दिर के सामान्य संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया जायेगा जिसकी खोज एक तीन सदस्यीय समिति करेगी। इसके साथ ही ट्रस्ट ने अस्थायी तौर पर अपने एक सदस्य कृष्ण मोहन को महासचिव नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण मोहन एक अवकाश प्राप्त वन अधिकारी हैं और श्रीराम मन्दिर आन्दोलन से भी जुड़े रहे हैं। उनकी छवि एक कुशल प्रशासक के रूप में भी देखी जाती है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की खोज के लिए ऐसी तीन सदस्यीय समिति घोषित की है जिसकी विश्वसनीयता पर कोई भी आसानी से सवालिया निशान न लगा सके। इसमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णु कान्त चतुर्वेदी व सुरेश ह्रावड़े होंगे। जाहिर है कि ट्रस्ट की यह कवायद श्रीराम मन्दिर में चढ़ावा चोरी की घटना उजागर होने के बाद उसके नाम पर लगे बट्टे को थामने की प्रक्रिया है जिससे ट्रस्ट की विश्वसनीयता लौट सके। चढ़ावा चोरी के बाद उत्तर प्रदेश समेत देश की विपक्षी पार्टियां जिस तरह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चारों तरफ से घेर रही हैं उसमें निश्चित रूप से राम भक्ति कम है और राजनीति यादा है क्योंकि 2027 के मध्य तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राय में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 2017 से चल रही है और उसकी लोकप्रियता भी बरकरार है परन्तु 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा से यादा सीटें जीत ली थीं इसलिए ये पार्टियां चाहती हैं कि विधानसभा चुनावों तक चढ़ावा चोरी का मुद्दा किसी न किसी रूप में जीवित रहे जिससे भाजपा को उसी के हिन्दुत्व व राम मन्दिर आन्दोलन की जमीन पर घेरा जा सके। दूसरी तरफ मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी के आरोप लगने के तुरन्त बाद जिस तरह मामले की पड़ताल करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया और उसे अपनी रिपोर्ट सिर्फ 15 दिन में देने के लिए कहा उससे विपक्षी पार्टियों को धक्का लगा और उन्होंने जांच दल गठित करने की प्रक्रिया को ही संदेह के घेरे में लेना शुरू कर दिया परन्तु जांच दल ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पांच दिन बाद ही देकर चढ़ावा चोरी की पुष्टि की और इसके लिए मन्दिर प्रबन्धन के आठ कर्मचारियों के साथ कुछ अन्य लोगों पर भी शक की अंगुली उठाई। इसके बाद आठ मन्दिर कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया गया। जांच दल ने जिन अन्य लोगों पर शक की अंगुली उठाई थी उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सबसे पहले निशाने पर आते थे क्योंकि महासचिव होने के नाते मन्दिर के सकल संचालन की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। इसके अलावा एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा कर्मचारियों की नियुक्ति करने में अग्रणी माने जाते थे। ट्रस्ट ने कर्नाटक के गोपाल राव को भी ट्रस्ट से अलग कर दिया जो कि विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में ट्रस्ट की बैठकों में भाग लेते थे। विपक्षी दल के नेता उन पर आरोप लगा रहे थे कि ट्रस्ट के केवल आमन्त्रित सदस्य होने के बावजूद वह मन्दिर प्रबन्धन में पूरा दखल रखते थे और उनका एक कथित भतीजा चढ़ावे का धन बोरियों में भरकर रेलगाड़ी से अपने राय कर्नाटक ले जाता था और अयोध्या वापस हवाई जहाज से लौटता था। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मन्दिर प्रबन्धन में चढ़ावे के धन की प्रतिदिन गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को जेल भेज कर सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। अतः ट्रस्ट की कल हुई बैठक के बाद इसके कोषाध्यक्ष गोविन्द गिरी महाराज ने साफ कर दिया है कि चोरी कांड की जांच करने वाले दल की हर सिफारिश को ट्रस्ट स्वीकार करेगा और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा जिससे लोगों में यह विश्वास पैदा हो सके कि उनकी श्रीराम के प्रति आस्था पर जिन लोगों ने भी चोट लगाने का काम किया है उनके साथ 'इह-लोक' में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जायेगी। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है तो उनकी आलोचना राजनीति को केन्द्र में रख कर की जा रही है क्योंकि जो लोग कल तक भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही काल्पनिक मान रहे थे और अयोध्या में मन्दिर निर्माण के आन्दोलनकारियों पर अपनी सरकार रहते गोलियां चलवा रहे थे वे आज राम के सबसे बड़े भक्त बने घूम रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को का?लनेमि की संज्ञा पहले ही दे चुके हैं परन्तु मूल मुद्दा चढ़ावा चोरी का है जिसे वाजिब तौर पर देश का कोई भी नागरिक या संगठन उठा सकता है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि मनघड़न्त आरोपों की बौछार लगा दी जाये और कहा जाने लगे कि उनकी दान की हुई कीमती वस्तुओं को भी गायब कर दिया गया है। ट्रस्ट की ओर से ब्यौरा दिया गया है कि मन्दिर को दान की गई हर कीमती वस्तु पूर्णतः सुरक्षित है और राम मन्दिर से जुड़े विभिन्न स्थलों की शोभा बढ़ा रही है। ट्रस्ट ने कल मन्दिर को मिले कुल दान का भी आंकड़ा जारी किया और चढ़ावे में चढ़ी कुल रकम की भी जानकारी दी। ब्यौरे में बताया गया है कि 31 मार्च, 2026 तक रकम के रूप में श्रीराम के चरणों में कुल 582 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जिसमें से 319 करोड़ रुपये मन्दिर के रख-रखाव आदि पर खर्च हुए और शेष धनराशि बैंकों में जमा है। मन्दिर के निर्माण के लिए कुल 3246 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 2370 करोड़ इसके निर्माण पर खर्च किये गये। इसके अलावा जो अन्य कीमती सामान जैसे सोने-चांदी से बनी वस्तुएं आदि हैं वे सभी पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की निद्रा भंग हो चुकी है और वे अपनी साख को बरकरार रखने के लिए पूरी पारदर्शिता बरतना चाहते हैं। इसलिए विपक्ष को भी अब आरोप लगाने से पहले सौ बार सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनके कथनों से कहीं हिन्दू समाज में उनकी छवि भी राम के नाम पर राजनीतिक मुनाफा कमाने वाले संगठनों के रूप में न उभरने लगे।

सम्पादकीय

कन्यादान योजना

गरीब परिवारों में बेटी की शादी हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रही है। दहेज, बारात और अन्य खर्चों का बोझ अक्सर माता-पिता को कर्ज के जाल में फंसा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार की योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना ऐसे ही गरीब श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों श्रमिकों की बेटियों के हाथ पीले करवाकर उनके सम्मान की रक्षा की है। कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र के एक कारखाने में काम करने वाले रमेश प्रसाद की कहानी भी इसी बदलाव की गवाह है। रमेश प्रसाद पिछले 15 वर्षों से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत एक चमड़ा फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी मासिक मजदूरी 18,000 रुपये है। इस सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बड़ी बेटी सीमा की शादी की उम्र होने पर रमेश की चिंता बढ़ गई थी। बेटी की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यह सोचकर उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। साहूकार से कर्ज लेता तो पूरी जिंदगी ब्याज भरते निकल जाती। इसी दौरान रमेश को फैक्ट्री के श्रमिक कल्याण अधिकारी से योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के बारे में पता चला। अधिकारी ने बताया कि यदि श्रमिक की मासिक मजदूरी 24,000 रुपये से अधिक न हो तो उसकी पुत्री की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है। यह सुनकर रमेश की आँखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत आवश्यक दस्तावेज जुटाए और श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दिया। योजना के तहत पात्रता की जांच के बाद रमेश का आवेदन स्वीकृत हो गया। बेटी की शादी की तारीख तय होते ही श्रम विभाग द्वारा 51,000 रुपये की धनराशि सीधे रमेश के बैंक खाते में भेज दी गई। यह राशि समय पर मिलने से रमेश का बड़ा बोझ हल्का हो गया। श्रमिक श्री रमेश ने बताया कि सरकार से मिली इस मदद से मैंने बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदा, बारातियों के खाने-पीने का इंतजाम किया और बिना किसी कर्ज के शादी संपन्न कराई। रमेश की बेटी सीमा की शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बारात आई, द्वारचार हुआ, कन्यादान हुआ और बेटी हंसी-खुशी विदा हुई। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि एक मामूली श्रमिक की बेटी की शादी इतने अच्छे से कैसे हो गई। रमेश गर्व से कहते हैं, आज मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश है। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वजह से संभव हुआ है। अगर यह योजना न होती तो शायद मैं बेटी की शादी इतनी इजत से नहीं कर पाता। रमेश की पत्नी सुनीता देवी भावुक होकर कहती हैं, हम गरीबों के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा डर दोनों होता है। सरकार ने हमारी बेटी का कन्यादान कर के हमारा डर खत्म कर दिया। अब हम दूसरी बेटी की शादी के लिए भी निश्चित हैं। सरकार ने हम जैसे श्रमिकों को सच में सहारा दिया है। योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना प्रदेश के लाखों पंजीकृत कारखाना श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। सरकार द्वारा श्रमिको के कल्याण के लिए संचालित योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अन्तर्गत 24,000 रुपये से कम मासिक आय वाले श्रमिकों को पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये की सहायता देती है। यह योजना साबित करती है कि सरकार श्रमिकों के सुख-दुख में साथ खड़ी है। रमेश की बेटी की हंसी और उनके परिवार का सम्मान ही योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना की सबसे बड़ी सफलता है।

सिस्टम की लापरवाही बयां करते खुले मैनहोल

देश में शहर कोई भी हो, कस्बा कोई भी हो, मैनहोल-बोरवैल का खुला रह जाना सामान्य सी बात है। ऐसे में बारिश के मौसम में अगर आप वाहन से या पैदल किसी सड़क से निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। सड़क के बीचोंबीच कोई मैनहोल खुला हो सकता है और आप मौत के कुएं में समा सकते हैं। हाल ही में मुंबई की बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। सड़क पर खुले पड़े मैनहोल ने एक और जिंदगी निगल ली। मामूली बारिश के बीच 55 वर्षीय शख्स सड़क पर चल रहा था, लेकिन खुले मैनहोल में गिरने के बाद वह सीधे मौत के मुंह में समा गया। सवाल यह है कि आखिर हर मानसून में मौत के ऐसे जाल क्यों बिछे रहते हैं? यह सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है। देशभर के कई शहरों में हर मानसून के मौसम में ऐसी ही घटनाएं होती हैं। कहीं मैनहोल के ढक्कन गायब रहते हैं, तो कहीं चेतावनी देने वाले साइन बोर्ड नहीं लगे रहते हैं। इन लापरवाही से पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन सवारों और बचों को सबसे यादा खतरा होता है। हर साल खुले मैनहोल, सीवर और नालों से जुड़े हादसों में 800-900 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। औसतन, हर दिन ऐसे हादसों में लगभग दो से तीन लोगों की मौत होती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे सैंकड़ों परिवारों की कहानियां छुपी हैं जिन्होंने ऐसे हादसों में किसी अपने को खोया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर हर मानसून के बाद भी हालात नहीं बदलते हैं तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? देशभर में मानसून की पहली बारिश होते ही सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं, ट्रेनें प्रभावित होती हैं, लोग घंटों जाम में फंस जाते हैं और कई बार तो घर से निकला इंसान जिंदा वापस भी नहीं लौट पाता। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो हर साल एक जैसी त्रासदी के बावजूद सबक नहीं लेती। मुंबई के साकीनाका का हादसा किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुआ। बीएमसी ने सफाई के लिए मैनहोल का ढक्कन खुला छोड़ा था, लेकिन वहां न बैरिकेट लगाए गए, न चेतावनी बोर्ड और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए। यह हादसा किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुआ। मुंबई जैसे शहर में कई दुःखद घटनाओं के बावजूद मैनहोल को सुरक्षित न कर पाना प्रशासनिक विफलता का सबूत नहीं तो और क्या है। 2017 में मुंबई में जाने-माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. दीपक अमरापुरकर की मौत चर्चा में आई थी, जब बारिश में मैनहोल में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। बीते दिनों पुणे के लोणी काळभोर इलाके में दो वर्षीय सोहम लखन कस्बे घर के बाहर खेल रहा था। सीवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए खोदे गए गड्ढों को बिना बैरिकेटिंग के खुला छोड़ दिया गया था। बारिश का पानी भरने से गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था। खेलते समय सोहम उसमें गिर गया और डूबने से मौत हो गई। बीती फरवरी को दिल्ली के रोहिणी स्थित बेगमपुर इलाके में मैनहोल में गिरने से 30 वर्षीय युवक बिरजू कुमार की मौत हो गई थी। इस घटना से पहले पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिरने से 25 वर्षीय बैंक कर्मचारी की मौत हो गई थी। हाल ही में इस से जुड़ी घटना छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली जहां 10 वर्ष का राहुल 65 घंटे से भी यादा मैनहोल में फंसा रहा। वहीं बिहार के पटना में कई जगह मैनहोल हैं जिन पर ढक्कन नहीं है जिसकी वजह से आए दिन वहां दुर्घटनायें होती रहती हैं। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि बारिश के मौसम में स्थानीय निकायों की लापरवाही व खराब इंजीनियरिंग के चलते कैसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है। ये असुरक्षित ड्रेनेज संरचना की घातकता को ही दर्शाता है। विडंबना है कि हमारा तंत्र सालभर सोया रहता है और जब बरसात शुरू होने को होती है, तब मरम्मत- नालों की सफाई के काम की औपचारिकता पूरी करता है। बहरहाल, इन सभी घटनाओं के मूल में एक बात तो समान है कि स्थानीय निकाय व प्रशासन जोखिमों का समय रहते अनुमान नहीं लगा पाते हैं। यह तथ्य सभी अधिकारी जानते हैं कि एक निश्चित समय पर मानसून आता है। बाकायदा समय-समय पर सूचना माध्यमों में मौसम विभाग द्वारा मानसून की भविष्यवाणी की जाती है लेकिन अधिकारी तब जागते हैं जब स्थितियां जटिल हो जाती हैं। वे इन हालातों को अप्रत्याशित आपात स्थिति के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। दरअसल,कई स्तरों पर होने वाली कमीशनखोरी व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अकसर ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं की जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 9 सालों में देश के भीतर मैनहोल या सीवर में गिरने से 1200 से यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे डरावनी बात यह है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 में इन मौतों के मामलों में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आया है। आंकड़ें बताते हैं कि साल 2023 में जहां मैनहोल और सीवर में गिरने से कुल 119 लोगों का मौत हो गई थी। इसके अगले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 61 प्रतिशत से यादा की छलांग लगाकर 192 पर पहुंच गया। खुले मैनहोल सिस्टम की लापरवाही की कहानी बयां करते हैं। मैनहोल में गिरकर जान गंवाने वालों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शामिल हैं। सड़क चलती कई महिलाओं को इन खुले मैनहोल ने अपना शिकार बनाया है। साल 2023 में मैनहोल में गिरने से जहां 11 महिलाओं की मौत हुई थी, वहीं अगले साल 2024 में ये संख्या बढ़कर 21 हो गई। साल 2022 इन नौ सालों में सबसे भयानक रहा, जब रिकॉर्ड 207 लोगों की मौत खुले सीवर या मैनहोल में गिरने की वजह से हुई। इसमें 179 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल थीं। वहीं 2023 में थोड़ी गिरावट के बाद 2024 में यह आंकड़ा 192 मौतों पर पहुंच गया। भारत में मानसून के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है। लोकल म्युनिसिपल बॉडी की लापरवाही और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर मानसून के मौसम में होने वाली दुर्घटनाओं का मुख्य कारण हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

सेंसरशिप की जंग में दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने ओटीटी नियमों को दी चुनौती, क्या पब्लिसिटी पाने का था सोचा-समझा प्लान?

एक ऐसी फिल्म जिसे सिनेमाघरों के परदे तक पहुंचाने और सेंसर बोर्ड की कैंची से बचाने के लिए मेकर्स ने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी, वह आखिरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई तो सही, लेकिन महज 48 घंटों के भीतर ही गायब हो गई। ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सतलुज को 3 जुलाई को चुपचाप ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम किया गया और दो दिनों के भीतर ही इसे भारत में कैटलॉग से हटा दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और पंजाब में 90 के दशक के उग्रवाद के काले दौर पर आधारित इस फिल्म के अचानक आने और जाने ने भारतीय डिजिटल मीडिया, सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने 5 ऐसे बड़े सवालों को जन्म दिया है, जिनके जवाब कानूनी और नैतिक रूप से बेहद पेचीदा हैं इस फिल्म का सफर बेहद विवादित रहा है। मूल रूप से इस फिल्म का नाम घल्लूघारा (जिसका पंजाबी में अर्थ नरसंहार होता है) रखा गया था। बाद में इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास पंजाब 95 के नाम से भेजा गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के संवेदनशील विषय को देखते हुए इसमें टाइटल, विजुअल्स और डायलॉग्स सहित कम से कम 127 कट्स लगाने की शर्त रख दी। मेकर्स ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन थिएटर में रिलीज का कोई रास्ता न देख आखिरकार याचिका वापस ले ली गई।

इसके बाद मेकर्स ने कानूनी खामियों या कहें रेगुलेटरी गैप का फायदा उठाने की रणनीति बनाई। सिनेमाघरों के लिए जहां छक्कष्ट का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत आते हैं, जहां सेल्फ-क्लासिफिकेशन (स्व-वर्गीकरण) का नियम लागू होता है। मेकर्स ने फिल्म का नाम बदलकर सतलुज किया और बिना प्री-सर्टिफिकेशन के इसे सीधे ZEE5 पर उतार दिया।

रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' में हुई शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस की एंट्री, निभाएंगी विलेन का दमदार किरदार

रोहित शेट्टी 'गोलमाल 5' के साथ इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में फिर से वापसी कर रहे हैं। फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार फिल्म में अक्षय कुमार की भी एंट्री हुई है। वहीं शरमन जोशी की वापसी हुई है। मेकर्स दर्शकों को कास्टिंग से जुड़े एक चौंकाने वाले ट्विस्ट से हैरान करने के लिए तैयार हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में 'द फैमिली मैन' और शाहरुख खान की 'जवान' फेम एक्ट्रेस प्रियामणि की भी एंट्री हुई है। प्रियामणि फिल्म में एक नेगेटिव रोल में नजर आएंगी, जो उनके पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग होगा। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, प्रियामणि गोलमाल 5 में एक नेगेटिव किरदार निभाएंगी। हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि इस कास्टिंग से कॉमेडी फ्रेंचाइजी में कुछ नयापन आएगा। अपनी अलग-अलग तरह की

भूमिकाओं के लिए मशहूर, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली इस एक्ट्रेस ने जयादातर इमोशनल और दमदार किरदार निभाए हैं। फिल्म की मुख्य विलेन के तौर पर उनका यह नया रूप रोहित शेट्टी की कॉमेडी और मस्ती-मजाक वाली फिल्मों में एक नया रंग जोड़ सकता है। रोहित शेट्टी के साथ प्रियामणि का यह पहला काम नहीं है। इससे पहले वह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के जबरदस्त डांस नंबर 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान में अजय देवगन के साथ भी काम किया है। गोलमाल 5 के साथ एक्ट्रेस एक बार फिर फिल्ममेकर और एक्टर के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इस बार उनका रोल बिल्कुल अलग है। गोलमाल 5 का प्रोडक्शन फरवरी 2026 में शुरू हुआ। मेकर्स ने मुख्य कलाकारों के साथ एक वीडियो जारी करके शूटिंग शुरू होने की घोषणा की। अजय देवगन के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और शरमन जोशी भी हैं। शरमन जोशी पहली फिल्म के बाद इस फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं। फिल्म में जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और अश्विनी कालसेकर जैसे कई पसंदीदा कलाकार भी लौट रहे हैं। यह फिल्म कन्फ्यूजन, कॉमेडी और जबरदस्त एंटरटेनमेंट का एक और दौर लेकर आएगी।

चंदा विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे अनुपम खेर, भक्ति में लीन होकर लिया आशीर्वाद

उत्तर प्रदेश का राम मंदिर इस समय चंदे को लेकर हो रहे विवादों के कारण चर्चा में है। इसी बीच, बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत देखा जा रहा है। इस वीडियो में वह अयोध्या की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। अनुपम खेर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अयोध्या पहुंचे हैं। काम शुरू करने से पहले उन्होंने राम मंदिर जाकर भगवान राम लला की विशेष पूजा-अर्चना की। जब वह मंदिर से बाहर आ रहे थे, तब वहां मौजूद मीडिया ने उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाए। अनुपम खेर को देखकर उनके चाहने वाले भी वहां जमा हो गए। एक्टर ने किसी को निराश नहीं किया और अपने फैंस के साथ खूब तस्वीरें और सेल्फी खिंचवाईं। अनुपम खेर बॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े और मशहूर अभिनेता हैं। वे अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करके अपनी कला का जादू बिखेरा है। अनुपम खेर जल्द ही अयोध्या में अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, जो अगले साल सिनेमाघरों में आएगी। अपनी इसी नई शुरुआत से पहले उन्होंने भगवान राम की पूजा की।

मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन- 76 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ देहांत, परिवार ने मौत की वजह साझा नहीं की

टेलीविजन होस्ट और एक्टर मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का बुधवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 76 वर्ष की थीं। मनीष पॉल की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की है। बयान में प्रशंसकों से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की गई है। हालांकि, परिवार की तरफ से अभी तक उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और अक्सर सोशल मीडिया पर उनके साथ तस्वीरें साझा करते रहते थे। मनीष पॉल की टीम ने बयान जारी कर बताया कि एक्टर की मां का दिल्ली में देहांत हो गया है। टीम ने कहा कि बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मनीष पॉल की मां का आज दिल्ली में निधन हो गया है।

हम आप सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोग मनीष और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मनीष पॉल अपनी मां उर्मिल पॉल के बहुत करीब थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते थे। साल 2022 में अपनी मां के जन्मदिन पर मनीष ने एक भावुक पोस्ट लिखा था। उन्होंने मां के साथ फोटो शेयर कर जीवन के प्रति उनका नजरिया बदलने के लिए धन्यवाद दिया था। मनीष ने लिखा था कि मुझे बिंदास रहना सिखाने के लिए आपका शुक्रिया। उर्मिल पॉल के परिवार में उनके पति जगमोहन पॉल, बेटी योति पॉल मोहन और दो बेटे मनीष पॉल और विवेक पॉल हैं। मनीष पॉल ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो जॉकी (आरजे) और वीडियो जॉकी (वीजे) के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग, होस्टिंग और स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने टेलीविजन पर राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, शशश...फिर कोई है और घर-घर में जैसे कई लोकप्रिय शोज में काम किया। उन्होंने फिल्मों में छोटे रोल से शुरुआत की थी। इसके बाद साल 2013 में आई फिल्म मिकी वायरस से उन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक कंप्यूटर हैकर मिकी का किरदार निभाया था। मनीष पॉल को भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय होस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने सा रे गा मा पा छोटे उस्ताद, झलक दिखला जा, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स और नच बलिये जैसे कई बड़े रियलिटी शोज को होस्ट किया है। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और एंकरिंग के लिए वे जाने जाते हैं। मनीष ने संयुक्ता पॉल से शादी की है। हाल ही में वे वरुण धवन के साथ फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में नजर आए थे।

प्रभास की फिल्म के सेट पर हादसा, राजेश शर्मा एडमिट - डॉक्टर बोले- अभी खतरे से बाहर नहीं; शूटिंग के दौरान कीड़े ने काटा

बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा को पैर में इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एक्टर प्रभास की फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी जहरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें पश्चिम बंगाल के ढाकुरिया स्थित मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी सह-कलाकार सुदीपा चटर्जी ने सोशल मीडिया पर एक्टर के परिवार की तरफ से हेल्थ नोट जारी कर यह जानकारी दी है। डॉक्टर के मुताबिक राजेश शर्मा अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। सुदीपा चटर्जी के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यह घटना हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई। राजेश शर्मा वहां प्रभास की आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वे सेट के पास पेड़-पौधों वाले इलाके में लोकल टेक्नीशियन्स के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पैर में किसी कीड़े या जहरीली मकड़ी ने काट लिया। उस समय मामला गंभीर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई मेडिकल मदद नहीं ली और काम जारी रखा। कीड़े के काटने के करीब छह घंटे बाद राजेश शर्मा के दाहिने पैर में तेज दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत खराब होने लगी।

इसके बाद भी उन्होंने कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ी। सफर के दौरान उन्हें तेज बुखार आ गया और वे काफी बेचैन हो गए। कोलकाता पहुंचने पर अगले दिन उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद परिवार ने उन्हें तुरंत ढाकुरिया के मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती हुए एक दिन से यादा का समय हो चुका है।

पैर में छाले पड़े, फेफड़ों में क्लॉट का खतरा

अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया कि कीड़े का इन्फेक्शन पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक फैल गया है। प्रभावित हिस्से पर बड़े-बड़े छाले पड़ गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक अभी स्थिति के बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राजेश शर्मा को डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों को चिंता है कि इन्फेक्शन की वजह से ब्लड क्लॉट (खून का थक्का) बन सकता है। अगर यह क्लॉट फेफड़ों तक पहुंचता है, तो जान का खतरा हो सकता है। राजेश शर्मा हाल ही में फिल्म भूत बंगला और कृष्णावतारम पार्ट 1- द हार्ट में नजर आए थे। वहीं अभिनेता प्रभास इन दिनों डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी की फिल्म फौजी और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि राजेश शर्मा इनमें से किस फिल्म के सेट पर शूटिंग कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। राजेश शर्मा अक्षय कुमार, सलमान खान समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। राजेश शर्मा अक्षय कुमार, सलमान खान समेत कई बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। हेल्थ नोट में बताया गया है कि इस मुश्किल समय में बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट्स फोरम और राजेश के दोस्त उनके साथ खड़े हैं। अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी लगातार परिवार के संपर्क में हैं और मदद कर रहे हैं। राजेश शर्मा की मां और पूरे परिवार ने संकट की इस घड़ी में साथ देने के लिए मीडिया और शुभचिंतकों का आभार जताया है। अस्पताल की टीम लगातार जांच कर रही है और गुरुवार को उनका ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा सकता है।

शीशमहल अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस, 6-फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को मिलेगा नया अवतार

नई दिल्ली । दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित 6-फ्लैगस्टाफ रोड का चर्चित सरकारी आवास जल्द ही नई जिम्मेदारी निभाता दिखाई देगा. कभी मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास के रूप में सुर्खियों में रहा यह परिसर अब सरकारी मेहमानों की मेजबानी और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है. दिल्ली सरकार ने इसे स्टेट गेस्ट हाउस और आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में औपचारिक फैसला लिया है. सरकारी स्तर पर हुई हालिया बैठक में तय किया गया कि इस परिसर का उपयोग केवल प्रशासनिक जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा. भविष्य में यहां सरकारी बैठकों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत, विशिष्ट अतिथियों का आवास तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे राजधानी में लंबे समय से महसूस की जा रही एक महत्वपूर्ण कमी पूरी होगी. अब तक दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई समर्पित स्टेट गेस्ट हाउस नहीं था, जहां विभिन्न रायों या विदेशों से आने वाले सरकारी प्रतिनिधियों को ठहराया जा सके. हर बार अलग-अलग व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता था. नए फैसले के बाद एक स्थायी और अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे सरकारी आयोजनों का संचालन भी अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा. योजना के तहत परिसर में आधुनिक अतिथि कक्ष, सम्मेलन हॉल, बैठक कक्ष और बहुउद्देशीय सभागार तैयार किए जाएंगे. यहां कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य कार्यक्रम, साहित्यिक आयोजन, सांस्कृतिक संवाद, सरकारी समारोह और विभिन्न विभागों के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा सकेंगे. सरकार का उद्देश्य इस परिसर को प्रशासनिक उपयोग के साथ-साथ राजधानी की सांस्कृतिक पहचान से भी जोड़ना है. अधिकारियों के अनुसार विकास कार्य इस तरह किए जाएंगे कि मौजूदा भवन में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जरूरत न पड़े. कोशिश रहेगी कि ऐतिहासिक महत्व वाले इस परिसर की मूल संरचना को अधिकतम सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएं. यह वही सरकारी आवास है, जो पिछले कुछ वर्षों में पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर हुए खर्च को लेकर राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा. भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनावी अभियान के दौरान शीशमहल नाम दिया था और विधानसभा चुनाव प्रचार में इसे प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया था. इस वजह से यह बंगला लंबे समय तक सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा में बना रहा. करीब आठ दशक पहले वर्ष 1942 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस विशाल सरकारी भवन का निर्माण कराया गया था. बाद के वर्षों में यह कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के आवास के रूप में उपयोग में रहा. वर्ष 2004 से 2008 तक तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम सिंह यहां रहे, जबकि बाद में विधानसभा के उपाध्यक्ष अमरीश गौतम को यह आवंटित किया गया. वर्ष 2015 से यह तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास बन गया. इस परिसर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण से जुड़े खर्च पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट सहित विभिन्न जांचों में प्रक्रियागत सवाल उठाए गए थे.

अरविंद केजरीवाल का मारुति-टोयोटा-हीरो को पत्र, 29 ऑटो कंपनियों से ई-20 फ्यूल पर पूछे कई सवाल

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखा। यह पत्र ई20 ईंधन के पुराने वाहनों में उपयोग को लेकर कंपनियों के विरोधाभासी बयानों पर केंद्रित है।

उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पत्र भेजने की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि तीन प्रमुख कंपनियों मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो को अलग से पत्र भेजा गया है। शेष 26 कंपनियों को एक अलग पत्र भेजा गया है। उन्होंने कंपनियों से सार्वजनिक तौर पर अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह कदम वाहन मालिकों की सुरक्षा और जानकारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। केजरीवाल ने 4 जुलाई को हुई सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। उस कॉन्फ्रेंस में इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि पुराने वाहनों में ई20 ईंधन का उपयोग सुरक्षित है। उन्होंने यह भी बताया था कि इससे माइलेज में करीब 3 से 5 फीसदी की कमी आ सकती है। हालांकि, प्रतिनिधियों ने दावा किया था कि वाहन को कोई नुकसान नहीं होगा। यह बयान सरकार की इथेनॉल मिश्रण नीति के समर्थन में था। केजरीवाल ने मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो को लिखे पत्र में इस विरोधाभास को उजागर किया है।

उन्होंने बताया कि इन कंपनियों की ओनर्स मैनुअल में स्पष्ट रूप से लिखा है। मैनुअल के अनुसार, 2023 से पहले निर्मित वाहनों में 10 फीसदी से अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। यह कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज और उनके प्रतिनिधियों के सार्वजनिक बयान के बीच एक बड़ा अंतर दर्शाता है। केजरीवाल ने इस विरोधाभास को छोटी गलती या मामूली विरोधाभास मानने से इनकार किया है। उन्होंने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है, जो लाखों वाहन मालिकों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कंपनियों से लिखित रूप में सार्वजनिक तौर पर अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। इस स्पष्टीकरण से उपभोक्ताओं को ई20 ईंधन के उपयोग के संबंध में सही जानकारी मिल सकेगी। यह कदम वाहन सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है।

दिल्ली-एनसीआर पर मानसून मेहरबान, नोएडा में झमाझम बारिश

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में मानसून मेहरबान है। बीते मंगलवार को दिल्ली में तेज बारिश हुई और आज बुधवार को भी सुबह से रुक-रुक कर कई इलाकों में बारिश हो रही है। नोएडा और फरीदाबाद में भी बारिश हो रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर जलभराव से यात्री परेशान दिखे। बीते मंगलवार को दिल्ली में दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला था। मानसून की जोरदार दस्तक से तापमान में गिरावट आई और मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि, इस राहत के साथ कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम भी देखा गया । मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की संभावना है। 8 से 13 जुलाई तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 8 और 9 जुलाई को दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह या दोपहर से पहले हल्की बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। आंधी और बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, 10 और 11 जुलाई को भी बादल छाए रहने के साथ दोपहर के आसपास हल्की बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। 12 और 13 जुलाई को मौसम में यादा बदलाव नहीं होगा और आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान करीब 32 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज हवाओं और आंधी के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी रह सकती है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी- कांग्रेस ने की चंपत राय की गिरफ्तारी की मांग; पीएम की चुप्पी और ट्रस्ट को लेकर क्या कहा?

नई दिल्ली। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर विवाद जारी है। इस बीच बुधवार को कांग्रेस ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रस्ट के सदस्यों के चयन में अपनी गलती के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जब राम मंदिर का श्रेय लेने की बात आती है, तब प्रधानमंत्री सबसे आगे रहते हैं। अब चढ़ावे की कथित चोरी की जिम्मेदारी लेने से वह क्यों बच रहे हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की मांग है कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, नया ट्रस्ट बनाया जाए और प्रधानमंत्री देश से माफी मांगें। मोदी जी, अपनी चुप्पी तोड़िए। यहां एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी पूरे मामले की जांच सप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तुरंत भंग कर उसकी जगह नया ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,नए ट्रस्ट के सदस्यों का फैसला शंकराचार्यों, सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज, निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधियों और विभिन्न संतों तथा महात्माओं की सहमति से होना चाहिए।

गोहिल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संतों और महात्माओं की जगह चंपत राय जैसे लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया। उन्होंने दावा किया, चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने से पहले राम मंदिर में हर दिन 16 से 18 लाख रुपये का दान आता था। लेकिन मामला सामने आने के बाद यह राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपये प्रतिदिन हो गई। उन्होंने कहा कि इससे यह शक पैदा होता है कि पहले हर दिन करीब 10 लाख रुपये का गबन किया जा रहा था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देशभर के करोड़ों लोगों ने भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा से दान दिया। लेकिन ट्रस्ट ने इस धन का सही हिसाब जनता के सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए इससे जुड़ी किसी भी कथित वित्तीय हेराफेरी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गोहिल ने कहा, सनातन परंपरा में शंकराचार्यों की राय का खास महत्व होता है। उन्होंने बताया कि शंकराचार्यों ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त को लेकर आपत्ति जताई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी लाभ के लिए उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी लगातार भगवान राम के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती रही है। कांग्रेस ने यह हमला उस समय किया, जब मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को चढ़ावे की कथित चोरी के विवाद के बीच चंपत राय के महासचिव पद और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार किए। ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से कायम करने और चढ़ावे की व्यवस्था में सुधार का वादा करते हुए ट्रस्ट ने यह भी घोषणा की कि मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए तीन सदस्यीय खोज समिति बनाई जाएगी।

अशोका एक्सप्रेस की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोटः पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादकः विजय कुमार

Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।

Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

आंगनवाड़ी केंद्रों को मिले 60 सेट आधुनिक उपकरण

भटनी देवरिया।

भटनी ब्लॉक में वितरण कार्यक्रम आयोजित, बचों के सर्वांगीण विकास पर दिया गया जोर

विकास खण्ड भटनी परिसर में आंगनवाड़ी केंद्रों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 60 सेट आंगनवाड़ी उपकरण संबंधित केंद्रों को सुपुर्द किए गए। इन उपकरणों के माध्यम से केंद्रों पर बचों की प्रारंभिक शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। वितरण कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र बचों के सर्वांगीण विकास की आधारशिला हैं। आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने से बचों के बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहीं केंद्रों पर संचालित गतिविधियों की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उपकरणों का समुचित रखरखाव एवं नियमित उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी साबिर अनवर, एडीओ पंचायत विंध्याचल सिंह, ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार यादव, धनंजय कुशवाहा, जनरंजन गौतम सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को बचों के बेहतर भविष्य के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सुबह-सुबह स्कूल पहुंचे डीएम, बिना सूचना गायब शिक्षामित्र को नोटिस

देवरिया।

डिजिटल उपस्थिति और पठन-पाठन की जांची गई जमीनी हकीकत बचों के पोषण और बुनियादी शिक्षा के स्तर में सुधार लाने की हिदायत

परिषदीय विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और धरातल पर उसकी वास्तविक स्थिति परखने के लिए जिला प्रशासन की सक्रियता लगातार बनी हुई है। बुधवार सुबह ठीक 7:45 बजे जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विकास खंड अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलई बेलवा और उससे संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह-सुबह कलेक्ट्रेट के शीर्ष अधिकारी के अचानक पहुंचने से विद्यालय स्टाफ और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका और बचों की डिजिटल अटेंडेंस के रिकॉर्ड की गहनता से पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में तैनात कुल छह शिक्षकों और दो शिक्षामित्रों के सापेक्ष एक शिक्षामित्र बिना किसी पूर्व सूचना के अपने दायित्व से अनुपस्थित पाए गए। इस अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित

शिक्षामित्र को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने उपस्थित शिक्षकों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी उपस्थिति पर निर्भर न रहें, बल्कि छात्र-छात्राओं की शत-प्रतिशत डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अभिभावकों से सीधा संपर्क स्थापित करें। उन्होंने कक्षा-कक्षों में जाकर बचों के अधिगम स्तर को भी देखा और शिक्षकों को प्रत्येक बचे को निपुण बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने वहां मौजूद बचों को मिल रहे पुष्टाहार, प्रारंभिक बाल शिक्षा (ईसीसीई) और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश दिया कि बचों के पोषण और स्वास्थ्य मानकों में किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। परिसर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुव्यवस्थित साफ-सफाई और एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर बल दिया, जिससे बचों का झुकाव स्कूल के प्रति बढ़ सके।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ, 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को मिलेगा लाभ

कुशीनगर। कुशीनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी से प्रसारित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र-छात्रा ?1200 की धनराशि हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में 10 लाख शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है और परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक और कल्याणकारी पहल है, जिससे अब आर्थिक अभाव के कारण किसी शिक्षक का उपचार प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने शिक्षकों से समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किए।

हरियाली की ओर कदम- देवरिया में 12 जुलाई को रोपे जाएंगे 39.91 लाख पौधे, सीडीओ ने परखीं तैयारियां

देवरिया।

जनपद के पर्यावरण संतुलन को सुदृढ़ करने और हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए आगामी 12 जुलाई को जिला प्रशासन एक वृहद वृक्षारोपण महाअभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत जिले में कुल 39,91,900 पौधे रोपने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्षों और कार्यदायी संस्थाओं की एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने स्पष्ट किया कि केवल पौधरोपण करना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि रोपे गए पौधों की सुरक्षा और उनकी उत्तरजीविता (जीवित रहने की दर) सुनिश्चित करना सभी विभागों की प्राथमिक जवाबदेही होगी। इस महाअभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट के निर्देशों के क्रम में विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य ग्राम्य विकास विभाग को 13,97,000 और वन एवं वन्यजीव विभाग को 13,46,000 पौधों का मिला है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को 4,32,000,

पंचायत भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेंगे सहजन, आंवला व नींबू के औषधीय पौधे रोपे गए पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश

पंचायती राज विभाग को 1,53,000 और पर्यावरण विभाग को 1,52,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर दो-दो सहजन के पौधे और हर पंचायत भवन परिसर में अनिवार्य रूप से आंवला, सहजन व नींबू के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा अमृत सरोवरों, चारागाहों, पशु आश्रय स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भी उपयुक्त प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और प्रबुद्ध वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बैठक में हरित विद्यालय और हरित ग्राम की अवधारणा को साकार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने आईजीआरएस (जनसुनवाई पोर्टल) की लंबित शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल दफ्तरों से रिपोर्ट न लगाएं, बल्कि मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से सीधा संवाद करते हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करें।

चाचा पर भतीजी से दुष्कर्म करने की प्रयास का आरोप,मुकदमा दर्ज

पटहेरवा कुशीनगर। एक चाचा पर भतीजी से दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाते हुये पीड़ित की माँ ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराई है।घटना 27 जून की शाम साढ़े तीन बजे की बताई जा रही है। पटहेरवा के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताई है कि वह कानपुर रहती है।वह गर्मी के छुट्टी में परिवार सहित अपने मामा घर गोपालगंज बिहार आई थी।इसी बीच उसे सूचना मिली कि उसके श्वसुर मोफीज आलम की तबीयत बहुत खराब है।घटना की सुबह लड़के व लड़की के साथ उन्हें देखने अपने श्वसुर के घर आ गयी।इसी बीच उसकी लड़की अपने दादा मोफीज आलम के पास बैठ कर बात कर रही थी कि उसके चाचा हसमत अली आ गए और उसे बुलाकर एक कमरे में ले गए और कमरा बंद कर दिए।फिर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगे।जिससे उसके कपड़े फट गये।लड़की के शोर सुनकर उसका लड़का आकिब बीचबचाव करने गया तो नाराज होकर लड़के व लड़की दोनों को गंभीर रूप से पिटाई कर दी।जिनका इलाज सीएचसी फाजिलनगर में कराई।पुलिस ने तहरीर पर आरोपित हसमत अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी रू 1,200 की धनराशि अंतरण

जौनपुर।

मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वाराणसी से आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ, विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति विद्यार्थी रू 1,200 की धनराशि अंतरण, शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू निष्पादन तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वछ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के सम्मान समारोह का कलेक्ट्रेट स्थित प्रेक्षागृह में सजीव प्रसारण देखा एवं सुना गया।

मा0 रायमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण श्री गिरीश चन्द्र यादव जी ने कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया। मा0 रायमंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव, मा0 रायसभा सांसद श्रीमती सीमा दिवेद्वी, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मनोरमा मौर्या, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री अजीत प्रजापति, डा0 अजय सिंह, जिलाधिकारी श्री सैमुअल पॉल एन, के द्वारा फीता काटकर, द्वीप प्रजवलित और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण कर कार्यक्रम की शुरूआत की गयी और सेल्फी प्वाइंट

पर सेल्फी भी लिया गया। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुछ, अगंवस्त्र और पौधा प्रदान कर किया गया। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के बचो द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान में स्वागत गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान मा0 जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षकों, शिक्षामित्र, अनुदेशक, स्पेशल एजुकेटर और रसोइयों को एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से 05 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए गए। मा0 रायमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों तथा शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य कार्मिकों के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को रू 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को बेहतर और समयबद्ध उपचार प्राप्त हो सकेगा तथा स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आर्थिक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि गुरुजनों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में सरकार का एक संवेदनशील एवं दूरदर्शी कदम है।

बेलवानिया चौराहे पर भीषण सड़क हादसा, आशा कार्यकर्ता समेत दंपति घायल

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर । हनुमानगंज थाना क्षेत्र के बेलवानिया चौराहे पर बुधवार शाम करीब 4 बजे एक सड़क हादसे में आशा कार्यकर्ता सहित पति-पत्नी घायल हो गए। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट आने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य दो घायलों का उपचार सीएचसी तुर्कहा में चल रहा है। जानकारी के अनुसार, खड्डा थाना क्षेत्र के रुदलपुर भुजौली निवासी रघु प्रजापति अपनी पत्नी पुष्पा देवी को इलाज के लिए बेलवानिया मिशन अस्पताल लेकर आए थे। उनके साथ गांव की आशा कार्यकर्ता माया मद्धेशिया भी थीं। चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दिए जाने पर वे सरपत नगर का रास्ता पूछ रहे थे। इसी दौरान बाइक मोड़ते समय पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में पुष्पा देवी के सिर में गंभीर चोट, रघु प्रजापति के पैर में चोट तथा आशा कार्यकर्ता माया मद्धेशिया की कमर में चोट आई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुर्कहा पहुंचाया।

मंदिर चंदा गबन मामले में कोई दोषी नहीं बचेगा, एसआईटी कर रही निष्पक्ष जांच - पीएन पाठक

- विजयपुर दक्षिणपट्टी में प्रेसवार्ता, ट्रस्ट प्रकरण पर सरकार का पक्ष रखा और विपक्ष पर भी साधा निशाना

पटहेरवा कुशीनगर। कुशीनगर सदर के विधायक पीएन पाठक ने कहा कि मंदिर चंदा गबन प्रकरण में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना सामने आने के 24 घंटे के भीतर एसआईटी गठित कर जांच शुरू करा दी थी। जांच निष्पक्ष ढंग से चल रही है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी ट्रस्ट से जुड़ा कोई व्यक्ति भ्रष्ट निकला है तो इसका दोष सरकार पर नहीं मढ़ा जा सकता। कानून अपना काम करेगा और आवश्यकता पड़ने पर बुल्डोजर जैसी कार्रवाई भी होगी। मंगलवार की देर शाम विजयपुर दक्षिणपट्टी स्थित रामकथा प्रवक्ता आचार्य कीर्तिकर महाराज के आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में विधायक ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े एक व्यक्ति की समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से 900 बार बातचीत होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के गलत आचरण से पूरी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और सरकार किसी भी दोषी को संरक्षण नहीं देगी। विधायक ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बिजली, शिक्षा, सड़क सहित विभिन्न विभागों की स्थिति किसी से छिपी नहीं थी, जबकि आज हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में बच्चों को जूते, मोजे, बैग, पुस्तकें सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से शिक्षकों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्पेशल टीईटी, डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का पारदर्शी लाभ, आयुष्मान भारत योजना और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके अनुशंसा पत्रों पर क्षेत्र के जरूरतमंदों को 60 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। एक प्रश्न के उत्तर में विधायक ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केवल ट्विटर और फेसबुक तक सीमित हैं तथा धरातल पर कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों और विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित

प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले—शिक्षकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

गोरखपुर। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी से संबोधन के सजीव प्रसारण के साथ हुई। इस दौरान प्रदेश भर में 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही 1.10 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग एवं स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र ?1200 की धनराशि हस्तांतरित की गई। इसके अलावा 10 लाख शिक्षक एवं संविदा कर्मियों के सामाजिक सुरक्षा हेतु भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू निष्पादित किया गया तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। सजीव प्रसारण के उपरांत प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद के माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षकों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों को प्रतीकात्मक चेक एवं कस्तूरबा बालिका विद्यालय की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्राओं को अध्ययन सामग्री किट प्रदान की गई। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि आज का दिन शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक है। यह योजना केवल एक पहल नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान और उनके सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण की आधारशिला हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि अब शिक्षकों को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के माध्यम से उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन और अधिक सुरक्षित एवं सशक्त होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और आज देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है।

चंडीगढ़ स्थित सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को देना होगा रूफटॉप सोलर अंडरटेकिंग फॉर्म

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित सरकारी मकानों में रहने वाले राय सरकार के कर्मचारी रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग से संबंधित अपना विकल्प/अंडरटेकिंग फॉर्म 10 जुलाई, 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराएं। ये निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से प्राप्त पत्र के बाद जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार की पहल के तहत सरकारी आवासीय भवनों में रूफटॉप सोलर प्रणाली की शत-प्रतिशत स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने-अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में सहमति प्रपत्र जमा करें, ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए हाउस अलॉटमेंट कमेटी, चंडीगढ़ के कार्यालय को समय पर भेजा जा सके। चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, सोलर उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेज) के संबंध में सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवेदनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कर्मचारियों को अंडरटेकिंग फॉर्म में निर्धारित विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। वे या तो रूफटॉप सोलर संयंत्र से उत्पादित बिजली का उपयोग करने तथा निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे इस सुविधा का उपयोग नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं या यह भी बता सकते हैं कि यह विकल्प उन पर लागू नहीं होता। अंडरटेकिंग में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग करने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें निर्धारित सोलर उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा तथा सोलर संयंत्र के रखरखाव के लिए अधिकृत कर्मियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति देनी होगी। वहीं, जो कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग नहीं करना चाहते, उनके मामले में रूफटॉप सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली को प्रचलित नियमों के अनुसार ग्रॉस मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से विद्युत वितरण लाइसेंसधारी को हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र कर्मचारियों से निर्धारित समयावधि में अंडरटेकिंग फॉर्म प्राप्त कर समय पर हाउस अलॉटमेंट कमेटी को भेजे जाएं। हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 जुलाई, 2026 तक किसी कर्मचारी का अंडरटेकिंग फार्म प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा सुविधा के उपयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान नहीं की है।

हरियाणा ने लोक अवसंरचना को दिव्यांगजनों, बुजुर्गों सहित सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाना किया सुनिश्चित

संवाददाता

चंडीगढ़ । लोक अवसंरचना को समावेशी और बाधा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने रायों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वभौमिक सुलभता मानकों का अनुपालन अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत सभी पात्र परियोजनाओं के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और भारत में सार्वभौमिक सुलभता के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और मानक, 2021 का अनुपालन करना आवश्यक होगा। यह कदम मौजूदा इमारतों में बाद में बदलाव करने के बजाय, योजना और डिजाइन के स्तर पर ही सुलभता सुविधाओं को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत लोक निर्माण विभाग और वास्तुकला विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नई सरकारी इमारतों के साथ-साथ नवीनीकरण और मरम्मत कार्यों सहित सभी पात्र परियोजनाओं के डिजाइन और निष्पादन में सुलभता मानकों को शामिल किया जाए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास लोक अवसंरचना का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें मिनी सचिवालय भवन, तहसील और उप-तहसील कार्यालय परिसर, सरकारी आवासीय क्वार्टर और पारगमन फ्लैट शामिल हैं। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं में सुलभता मानदंडों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि योजना और डिजाइन के चरण में ही सुलभता उपायों को एकीकृत करने से (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित होगा, साथ ही निर्माण के बाद होने वाले महंगे रैट्रोफिटिंग (संशोधनों) की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांतों को अपनाने से ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी जो हर नागरिक के लिए समावेशी, टिकाऊ और सुलभ हो। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक सुलभता केवल दिव्यांगजनों तक ही सीमित नहीं है। सार्वभौमिक सुलभता सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया बुनियादी ढांचा वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अस्थायी रूप से चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को भी लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि रैंप, सुलभ प्रवेश द्वार, लिफ्ट, स्पर्श पथ, हैंड्रेल्स, सुलभ शौचालय और उचित साइनबोर्ड जैसी विशेषताएं सरकारी भवनों को समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और उपयोग में आसान बनाती हैं। उन्होंने कहा कि लोक अवसंरचना में सुलभता को मुख्यधारा में लाने से न केवल (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, बल्कि समावेशी और समान विकास के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी। इस निर्णय के साथ हरियाणा ने अपने बुनियादी ढांचे के नियोजन को सुगम्य भारत अभियान (के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप संरेखित किया है। इस कदम से भविष्य की लोक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सार्वभौमिक सुलभता को बाद के विचार के बजाय एक मुख्य डिजाइन आवश्यकता बनाकर एक नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है।

ट्रंप के एक बयान के बाद अचानक भरभराकर गिरा शेयर बाजार

नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव निवेशकों की चिंता का कारण बने। इसके चलते बाजार में जमकर बिकवाली हुई और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 2 फीसदी से अधिक गिरकर बंद हुए। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार पर दबाव बना हुआ था, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में बिकवाली और तेज हो गई। निवेशकों ने जोखिम वाले शेयरों से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे बाजार में गिरावट और बढ़ गई। बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान भी रहा, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ हुए अंतरिम शांति समझौते के खत्म होने की बात कही। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में दोबारा तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई। निवेशकों को डर है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे तेल की कीमतों में और तेजी आने की संभावना है, जिसका असर दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं और शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों के लिए चिंता का विषय है। तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर भी दबाव आ सकता है। इसी वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और उन्होंने बाजार में बिकवाली बढ़ा दी। दोपहर 2:18 बजे तक सेंसेक्स 1,601 अंक गिरकर 76,580 पर आ गया, जबकि निफ्टी50 में 472 अंकों की गिरावट हुई और यह अहम 24,000 के स्तर से नीचे चला गया।

बाजार में आई इस गिरावट से निवेशकों की लगभग 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति खत्म हो गई, जिससे BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 476 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया। सेंसेक्स की सभी कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे; इनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारती एयरटेल के शेयरों में 2-4 फीसदी की गिरावट देखी गई। दलाल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली के बीच, बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने वाला इंडिया VIX 26फीसदी बढ़कर 14.67 पर पहुंच गया, जो निवेशकों की बढ़ती चिंता को दिखाता है। व्यापक बाजार पर भी दबाव देखा गया

क्या टेस्ट के बाद पाकिस्तान के टी20 कप्तान भी बनेंगे बाबर आजम? पीसीबी कर रहा विचार

कराची । पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक बार फिर टी20 टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) आगामी मैचों और दौरों को देखते हुए बाबर को दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी के एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद पीसीबी खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है। अगर इस फैसले को मंजूरी मिलती है तो बाबर आजम मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा की जगह लेंगे, जो बदलाव के दौर में टीम की कमान संभाल रहे हैं। यह घटनाक्रम बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी वापस मिलने के ठीक बाद सामने आया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक पर सभी प्रारूप में भरोसा जताने का मन बना रहा है। हालांकि पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट का कहना है कि आगामी अंतरराष्ट्रीय मैचों और भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंटों की तैयारियों के बीच बाबर टी20 टीम की कमान संभालने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बाबर आजम इससे पहले भी तीनों प्रारूप में पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में काफी सफलता हासिल की थी, जिसमें 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल और 2022 के संस्करण में उपविजेता बनना शामिल है। कप्तान के तौर पर उनका जीत का प्रतिशत भी पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर कप्तानी में बदलाव होता है तब भी सलमान अली आगा टीम की योजनाओं का अहम हिस्सा बने रहेंगे, क्योंकि पीसीबी टीम में उनके योगदान को काफी महत्व देता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पीसीबी अपनी आंतरिक चर्चा पूरी करने और अगली टी20 सीरीज के लिए टीम को अंतिम रूप देने के बाद ही इस पर कोई आधिकारिक घोषणा करेगा। तब तक बोर्ड ने इस मामले पर चल रही अटकलों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

क्या तिलक को बाहर कर सैमसन की होगी वापसी? बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की कितनी संभावना

ब्रिस्टल । श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन दौरे पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कभी गेंदबाजों को महंगा साबित होना पड़ रहा है तो कभी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में पूरी भारतीय टीम 76 रन पर ही ऑलआउट हो गई और उसे इस प्रारूप में रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच गुरुवार को खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा था।दूसरे और तीसरे टी20 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा जिससे टीम इंग्लैंड से 0-2 से पिछड़ गई है। भारत अब यहां से इस सीरीज को अपने नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास सीरीज में बराबरी हासिल करने का मौका है। भारतीय टीम अगर अगले दोनों मैच जीत लेती है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। इंग्लैंड दौरे से पहले टीम को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से हार मिली थी। भारतीय टीम इंग्लैंड के मुश्किल हालात में ढलने के लिए संघर्ष कर रही है और टीम यह मैच हार गई तो सीरीज भी गंवा देगी। टीम चयन को लेकर सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर है। उन्हें दूसरे और तीसरे टी20 से बाहर कर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था। इस युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन अब तक टीम के बाकी खिलाड़ियों से न तो खराब रहा है और न ही बहुत अच्छा। चूंकि टीम अभी 0-2 से पीछे चल रही है इसलिए भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सैमसन की वापसी की संभावना से इनकार नहीं किया है। तीसरे टी20 में करारी हार के बाद ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों ने 'वी वांट संजू' (हमें संजू टीम में चाहिए) के नारे लगाए। अब सलामी बल्लेबाजी जोड़ी को छेड़े बिना सैमसन को टीम में शामिल करने और सूर्यवंशी को बिना किसी दबाव के अपना हुनर दिखाने का मौका देने के लिए मध्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की जगह पक्की मानी जा रही है क्योंकि प्रबंधन को उनकी विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी शैली पर भरोसा है, लेकिन उपकप्तान तिलक वर्मा की जगह पर सवाल उठ सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी किस्मत को बदलने के लिए बदले हुए बल्लेबाजी क्रम के साथ सैमसन पर भरोसा करेगा। इस स्थिति में तिलक प्लेइंग-11 से बाहर हो सकते हैं और सैमसन को उनके स्थान पर उतारा जा सकता है। भारत की चिंता सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं है, बल्कि वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म ने भी उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। भारत ने तीसरे टी20 में रवि बिश्नोई को एकादश से बाहर कर दिया था। क्या अब चौथे टी20 में टीम प्रबंधन वरुण को भी बाहर बैठा सकता है? वरुण की जगह वाशिंगटन सुंदर को आजमाया जा सकता है जो गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी विकल्प देते हैं। अब यह देखना होगा कि लगातार हार के बाद श्रेयस और टीम प्रबंधन प्लेइंग-11 में बड़ा बदलाव करने का जोखिम उठाते हैं या इसी संयोजन पर भरोसा बरकरार रखते हैं।

इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा/संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

इंग्लैंड - फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉवसन, जोश टंग, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर।

क्या संजू सैमसन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो गए हैं? गौतम गंभीर के बयान से मिले संकेत

लंदन ।

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार प्लेइंग-11 से बाहर रहने और जिम्बाब्वे दौरे की टीम में जगह नहीं मिलने के बाद संजू सैमसन के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि विकेटकीपर बल्लेबाज को उनकी भूमिका को लेकर पूरी स्पष्टता दे दी गई है और मौजूदा सीरीज में उनकी वापसी की संभावना भी खत्म नहीं हुई है। भारत को तीसरे टी20 मुकाबले में 125 रन से करारी हार मिलने के बाद गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमसन के भविष्य पर खुलकर बात की। गौतम गंभीर ने कहा कि सैमसन से उनकी व्यक्तिगत बातचीत हो चुकी है और उन्हें टीम प्रबंधन का रुख साफ तौर पर बता दिया गया है। उन्होंने कहा, संजू सैमसन को जितनी स्पष्टता दी जानी चाहिए थी, वह मैंने उन्हें दे दी है।

वह बातचीत एक मुख्य कोच और खिलाड़ी के बीच हुई है। उस बातचीत में क्या कहा गया, यह मैं सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करूंगा। गंभीर ने सैमसन के योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि टीम प्रबंधन उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह स्पष्ट हैं कि संजू ने भारत के लिए, खासकर विश्व कप के दौरान, शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन कई बार किसी खिलाड़ी की मौजूदा फॉर्म को भी देखना पड़ता है। ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि वह इस सीरीज में वापसी नहीं कर सकते। टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन को आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के पहले टी20 में क्रमशः 5, 0 और 1 रन की पारियों के बाद प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया। इसके अलावा जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी चयनकर्ताओं ने सैमसन की जगह प्रभसिमरन सिंह को चुना, जिन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। गंभीर ने स्पष्ट किया कि टीम चयन सिर्फ नाम या पिछले प्रदर्शन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि मौजूदा फॉर्म और सर्वश्रेष्ठ संयोजन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, आखिरकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे यादा मायने नतीजों के होते हैं। हमें जो संयोजन टीम को जीत दिलाने के लिए सबसे बेहतर लगता है, हम उसी संयोजन और उसी प्लेइंग-11 के साथ उतरते हैं।

उन्होंने आगे कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर खिलाड़ी को अपनी जगह खुद अर्जित करनी होती है। भारत के लिए खेलने का अधिकार भी प्रदर्शन के दम पर ही मिलता है। गंभीर के इस बयान से साफ है कि संजू सैमसन को टीम प्रबंधन ने पूरी स्थिति समझा दी है। हालांकि फिलहाल उन्हें बाहर रखा गया है, लेकिन अगर उनकी फॉर्म और टीम की जरूरतें मेल खाती हैं तो इंग्लैंड सीरीज में भी उनकी वापसी संभव है।

करारी हार के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, कहा- यह प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं

भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से 125 रन की करारी हार के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन को ''बेहद खराब'' करार दिया और कहा कि इस तरह का प्रदर्शन कतई स्वीकार्य नहीं है। अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं जीता है। मंगलवार को खेले गए मैच में तो उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा जब टीम 202 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 11.4 ओवर में 76 रन पर आउट हो गई और उसे रन के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। गुरुवार को ब्रिस्टल में चौथा टी20 मैच और शनिवार को साउथेम्प्टन में अंतिम मैच खेला जाएगा। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अय्यर का मानना था कि ट्रेंट ब्रिज की इस पिच पर गेंदबाजों को 200 रन नहीं देने चाहिए थे। उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह 200 विकेट वाली पिच थी। हमने पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए और इसी वजह से हम पिछड़ गए। आप कितनी भी योजना बना लें, लेकिन मैदान पर उतरने के बाद आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। मुझे लगा कि हार्ड लेंथ पर शॉट लगाना मुश्किल था और हम उसे ठीक से अंजाम नहीं दे पाए। भारतीय कप्तान ने कहा, ''हमें अब अतीत के बारे में नहीं सोचना होगा और मजबूत वापसी करनी होगी। हमारे प्रत्येक खिलाड़ी को इस पर विचार करना होगा कि वह किस तरह से योगदान दे सकता है। वापसी के रोडमैप पर बात करते हुए कप्तान ने टीम के सभी खिलाड़ियों को कड़ा संदेश दिया है। अय्यर ने कहा, ÷हमें अब अतीत के इस बुरे प्रदर्शन को पीछे छोड़ना होगा और मजबूत मानसिक स्थिति के साथ वापसी करनी होगी।

अर्जेंटीना से हार के बाद मिस्र ने फीफा से की शिकायत; रेफरी को विश्व कप से बाहर करने की उठाई मांग

अटलांटा । मिस्र फुटबॉल महासंघ ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 में अर्जेंटीना से 3-2 की हार के बाद रेफरी फ्रांस्वा लेटेक्सियर के फैसलों के खिलाफ फीफा में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। मिस्र की टीम एक समय 2-0 की बढ़त पर थी और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी। हालांकि, अर्जेंटीना ने अंतिम क्षणों में शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इस दौरान लियोनेल मेसी ने एक गोल किया और एक गोल में अहम भूमिका निभाई, जबकि स्टॉपेज टाइम में एन्जो फर्नांडीज ने विजयी गोल दागा। मुकाबले के बाद मिस्र खेमे ने कई अहम फैसलों पर नाराजगी जताई। टीम का दावा है कि डुक्रसमीक्षा के बाद उसका एक गोल रद्द कर दिया गया, जबकि अर्जेंटीना के निर्णायक गोल से पहले मिली पेनल्टी की अपील की डुक्रसे समीक्षा तक नहीं की गई। स्पेनिश प्रकाशन डियारियो एएस की रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष ह्यानी अबू रिदा ने फ्रांसीसी रेफरी फ्रांस्वा लेटेक्सियर और उनकी ऑफिशिएटिंग टीम के खिलाफ फीफा में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, मिस्र फुटबॉल महासंघ ने उन फैसलों की जांच की मांग की है जिन्हें वह विवादास्पद मानता है। इसके साथ ही महासंघ ने आधिकारिक तौर पर यह भी अनुरोध किया है कि फ्रांसीसी रेफरी और उनकी पूरी ऑफिशिएटिंग टीम को टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों से हटा दिया जाए। इससे पहले मिस्र के मुख्य कोच हसन ने भी रेफरी के कई फैसलों पर नाराजगी जताई थी।

उनका कहना था कि मैच का नतीजा सिर्फ मैदान पर हुए खेल से तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा विश्व चैंपियन से हर मामले में बेहतर खेले, लेकिन नतीजा मैदान के अंदर और बाहर के कारकों से प्रभावित हुआ। शायद वे चाहते थे कि विश्व चैंपियन टूर्नामेंट में बने रहें। शायद वे चाहते थे कि मेसी आगे खेलते रहें। हसन ने कहा कि फुटबॉल में कई बार तकनीकी पहलुओं से परे भी बाहरी प्रभाव देखने को मिलते हैं और विश्व चैंपियन को हर स्तर पर समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि आज हमें न सम्मान मिला और न ही फेयर प्ले। एक पेनल्टी नहीं दी गई, उसकी समीक्षा भी नहीं हुई। हमारा दूसरा गोल भी किसी कारण से रद्द कर दिया गया।

हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और यह अन्याय है।

माननीय प्रधानमंत्री-भारत सरकार, श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री, श्रीमती रेखा गुप्ता जी

पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का कमाऊ पूत

डी.एस.आई.आई.डी.सी के

ई-एन-सी (यू.सी) सच्चिदानंद शरण,

अधिशासी, सहायक व कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा विकास एवं निर्माण कार्य में फर्जी बिल लगाकर किए करोड़ो का बंदर बांट शरण के चहिते अभियंताओं ने

अनाधिकृत कॉलोनी के विकास कार्यो में फर्जी बिल ठेकेदार से बनवाकर किए करोड़ो के घोटाले भ्रष्टाचार की जांच

निदेशक, सीबीआई, भारत सरकार से कराई जाएं

E-N-C (UC-1) सच्चिदानंद शरण पर लागू नही होती तबादला निती, वर्षो से लगा रहे है एक ही कार्यालय में भ्रष्टाचार की यमुना में डूबकी, पूर्व केजरीवाल सरकार से मर्ज करवा लिया उपरोक्त विभाग में 20प्रतिशत कमिशनखोरो का अड्डा बना कार्यालय-लाजपत नगर, दिल्ली

लाजपत नगर कार्यालय में RTI & APPEAL आवेदन नही लेते, करते है अभद्र व्यवहार

E-N-C (UC-1), S.N.SARAN साहब मिलने से करते है इंकार,

RTI कार्यकर्ता, पत्रकार एवं समाजसेवको पर आने-जाने पर लगाया प्रतिबंध

दोनो हाथो से लूट रहे है दिल्ली सरकार खजाने को।

DSIIDC, CD-04, 05, 06, 07, 08, 24 के अधिशासी, सहायक, कनिष्ठ अभियंताओं ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के अनाधिकृत कॉलोनी में विकास एवं निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री और फर्जी बिल लगाकर कर रहे है अपना समाजवाद दूर!

निवेदक: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा (विज्ञापन)